भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 751

07 फरवरी, 2023 को उत्तरार्थ

विषय: भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति योजना

751. श्री विष्णु दयाल राम:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति (बीपीकेपी) योजना के अंतर्गत प्रति किसान आय और क्रय शक्तियों में वृद्धि का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत प्रति किसान उत्पादन लागत में कुल कितनी कमी आई है;

(ग) किसानों की समग्र वृद्धि इस प्रकार योजना के प्रभाव का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त योजना को आरंभ करने से पहले किसानों की प्रारंभिक स्थिति का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (घ): परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के तहत भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति (बीपीकेपी) को वर्ष 2020-21 से कार्यान्वित किया जा रहा है ताकि गैर-रासायनिक खेती को बढ़ावा दिया जा सके, जिसमें बायो-मास मल्चिंग, गाय के गोबर-मूत्र से बने यौगिकों और अन्य पौध आधारित सामग्रियों के उपयोग पर जोर देते हुए खेत पर बायोमास पुनर्चक्रण पर निर्भरता के माध्यम से पारंपरिक स्वदेशी पद्धतियों का उपयोग किया जाता है।

चूंकि बीपीकेपी के तहत रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों तथा अन्य ऑफ फार्म आदानों का उपयोग नहीं किया जाता है, इसलिए यह अनुमान लगाया जाता है कि इन घटकों पर बचत के कारण किसानों की उत्पादन की कुल लागत में भारी कमी आई है। इसके अलावा, खेत पर संसाधनों के प्रबंधन ने भी किसानों को आर्थिक लाभ प्रदान किया है। बीपीकेपी के तहत क्लस्टर गठन, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा निरंतर प्रारंभिक सहायता, प्रमाणन और अवशेष विश्लेषण के लिए 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रति हेक्टेयर 12200/- रूपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

बीपीकेपी योजना आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है तथा बीपीकेपी के तहत प्राकृतिक खेती के लिए 4.09 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को अनुमोदन दिया गया है। इन राज्यों को 55.99 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। हालांकि, उत्पादन लागत में कमी और बीपीकेपी के तहत प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के समग्र विकास पर इस योजना के प्रभाव का पता लगाने के लिए कोई औपचारिक अध्ययन नहीं किया गया है।

****